

## सुदृढ़ वित्तीय सेवा क्षेत्र : विकास कायम रखने की अनिवार्यताएं\*

एस.एस. मूंदड़ा

आप सभी को सुप्रभात !

मुझे प्रसन्नता है कि आजकी सुबह मुझे इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों से बात करने का अवसर मिला है और इस अवसर के लिए मैं आईसीएआई को धन्यवाद देता हूँ। जैसाकि आप जानते हैं कि आज की सुबह इस सत्र का थीम 'वित्तीय सेवा क्षेत्र - कायम रखने योग्य विकास हेतु कार्यसूची' है और मुझ जैसे व्यक्ति को इसपर बात करनी है जिसने अपना संपूर्ण पेशेवराना जीवन बैंकिंग क्षेत्र की सेवा में बिताया है - पहले कमर्शियल बैंकर और अब केंद्रीय बैंकर के रूप में, मैं खासतौर से बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में बात करूंगा।

### प्रस्तावना

2. मैं अपनी बात की शुरुआत दक्षिण कोरिया से करूंगा और आपको पीछे वर्ष 1997 में ले जाऊंगा। आपके बीच उपस्थित 'भूरे बाल वाले' लोगों को याद होगा कि वर्ष 1997 तक की अवधि में कोरियाई अर्थव्यवस्था तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र की अन्य 'शेर' जैसी अर्थव्यवस्थाएं वार्षिक रूप से 6 से 10 प्रतिशत के बीच की गति से विकास कर रही थीं। तीव्र विकास और विस्तार की उम्मीदों के प्रति उनमें तेजी थी, कोरिया में चेबोल्स (परिवार जिसके पास कारोबार के समूह का स्वामित्व है) ने औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें निवेश हेतु बहुत बड़ी विदेशी रकम की उगाही की। लेकिन, जैसे ही अर्थव्यवस्था में मंदी आई, कर्ज की समस्या गंभीर होने लगी और उनमें से एक चेबोल जिसका नाम हनबो था, 6 बिलियन अमरीकी डालर के बोझ से तबाह हो गया। कंपनी ने 1993 में विश्व का पांचवां सबसे बड़ा इस्पति संयंत्र लगाने का निर्णय लिया किंतु उसकी लागत 2700 बिलियन वॉन से बढ़कर 5700 बिलियन वॉन हो गई और तभी इस्पति की मांग मंद पड़ गई। स्थिति तब और खराब हो गई जब जुलाई 1997 में कोरिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी 'किया' को दिवालिया होने से बचने के लिए आयात स्थिति में बैंक से ऋण

\* श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भा.रि.बैंक द्वारा 9 अगस्त 2015 को हंदैर में आईसीएआई के 'लेखांकन पेशा: उत्कृष्टता में अग्रणी' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए भाषण का मुख्य अंश। श्री संजीव प्रकाश द्वारा प्रदान की गई सहायता के प्रति आभार।

लेना पड़ा। इन घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय साख एजेंसियों को कोरियाई बैंकों की रेटिंग कम करने के लिए बाध्य कर दिया क्योंकि चेबोल्स के पास बैंकों का बहुत अधिक एक्सपोजर था और इस प्रकार कोरिया में वित्तीय मंदी का दौर शुरू हो गया था।

3. 'एशियाई वित्तीय संकट' जिसे बड़े पैमाने पर जाना जाता है, इसकी शुरुआत थाइलैंड में 5 फरवरी, 1997 से हुई थी, जब एक थाई संपत्ति विकासक अपने यूरोबांड ऋण पर निर्धारित ब्याज भुगतान तिथि का उसका भुगतान नहीं कर सका। थाइलैंड में कारोबारी मॉडल इस प्रकार के बने हुए थे कि उसमें यूरोबाण्ड जारी किए जाते थे जो डालर मूल्यवर्ग में होते थे ताकि डालर मूल्यवर्ग के कर्ज तथा थाई कर्ज के बीच के ब्याज दर अंतर का फायदा मिल सके और उससे प्राप्त होने वाली आमदनी संपत्ति विकास में लगाई जाती थी। जनवरी 1998 तक इस प्रकार की अनेक अर्थव्यवस्थाओं में स्टॉक बाजार अपने 70 प्रतिशत से अधिक का मूल्य खो चुके थे, उनकी करेंसियों का भी उसी मात्रा में मूल्य-हास हुआ और कई को आइएमएफ से सहायता लेनी पड़ी।

4. प्रारंभ में इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख करके मैं यह रेखांकित करना चाहता हूँ कि संकट के समय में किस प्रकार से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। समस्या प्रायः इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि एक बैंक किसी खास क्षेत्र या क्षेत्रों में बहुत अधिक पैसा लगा देता है (धन का संकेंद्रण हो जाता है), कारपोरेट अपने लीवरेज कई गुना बढ़ा देते हैं और अधिक क्षमता पैदा करने के लिए निवेश करते जाते हैं। जोखिमों को इसके बावजूद भी शायद नियंत्रित किया जा सकता है, बशर्ते बैंक की पूंजी की स्थिति मजबूत हो, लेकिन यदि मजबूत नहीं है तो जोखिम चारों ओर से प्रकट होने लगता है। घरेलू बाजार को विकास के लिए विदेश से उधार लेकर धन लगाने से लीवरेज की स्थिति बन जाती है और यह इस कहानी में एक और नया मोड़ पैदा कर देती है। एक बार घरेलू करेंसी का मूल्य-हास होना शुरू हुआ, तो फिर कारपोरेट्स जिनके पास भारी मात्रा में असुरक्षित (अनहेज्ड) पोर्जिशंस हैं, के लिए ऋण का चुकाना एक चुनौती बन जाता है। यदि विभिन्न कारपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर उधार लिए गए हैं तो यह ऋण-संकट बड़ी आसानी से एक पूर्ण-रूपेण करेंसी संकट को उत्पन्न कर देगा।

5. वित्तीय संकट खासतौर से करेंसी, ऋण या बैंकिंग संकट के रूप में होता है जिसका अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहां यह प्रश्न उठता है कि वित्तीय संकट आते क्यों हैं? निःसंदेह इसके कई कारण हो सकते हैं - कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक और कुछ

राजनैतिक। इस विषय पर हम विस्तार से किसी अन्य समय चर्चा करेंगे, सिर्फ इतना कहना पर्याप्त होगा कि सभी प्रकार के संकट का मूल कारण संरचना में निहित कमजोरियां होती हैं और स्वतः नियंत्रण की प्रक्रिया को सभी ओर लागू कर पाने में नाकामी तथा स्थापित संरचना का अनुपालन न कर पाना होता है। वस्तुतः, 2008 के वित्तीय संकट का आधार एक लंबे समय से चली आ रही सहज मौद्रिक नीति रही, फलस्वरूप जोखिमों का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सका, बाजार के बिचौलियों द्वारा कमाई करने की तलाश थी और बाजार के व्यवहार पर पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं था।

### आज का भारत

6. आज भारतीय परिदृश्य की ओर देखें तो कोई भी उसकी तुलना 1997-98 के दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की घटनाओं से करने से बाज नहीं आ पाएगा, हालांकि प्रभाव की तीव्रता काफी भिन्न थी। मैं इस्पात क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। भारत में इस्पात क्षेत्र को पिछले पांच वर्षों से अधिक अवधि में दिए गए बैंक ऋण 21 प्रतिशत सीएजीआर थे और प्रत्येक बैंक की ऋण-बहियों में मोटे तौर पर इसका हिस्सा 4 से 9 प्रतिशत के बीच है। बैंकों का इस्पात क्षेत्र में कुल एक्सपोजर 3 लाख करोड़ रुपए है जबकि क्षेत्र के भीतर इन कंपनियों की निवल बिक्री 3 लाख करोड़ रुपए है जिसमें ईबीआईडीटीए 37,000 करोड़ रुपए शामिल है। इस क्षेत्र में दबावग्रस्त आस्तियों का स्तर 27 प्रतिशत से अधिक हो गया है। बड़ी-बड़ी क्षमता वाली कंपनियां ठप पड़ गई हैं क्योंकि विश्व/घरेलू स्तर पर मांग कमजोर हो गई है। इसके अलावा अधिक लीवरेज का इस्तेमाल करते हुए क्षमता विस्तार तो कहीं अधिक कर लिया गया है। ये बातें निश्चित रूप से चिंता पैदा करती हैं।

7. उधार लेने वाले कारपोरेट्स द्वारा अत्यधिक लीवरेज के इस्तेमाल की समस्या केवल इस्पात क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह दिया गया है कि भारत के कुल ऋण का 36.9 प्रतिशत जोखिमपूर्ण है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, जबकि भारतीय बैंकों के पास हानि उठाने का बफर मात्र 7.9 प्रतिशत के बराबर है, जो उक्त अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। क्रेडिट सुइसे द्वारा 3700 कंपनियों के नमूना जांच का विश्लेषण यह दर्शाता है कि इन कंपनियों के 37 प्रतिशत ऋण ऐसी कंपनियों के हैं जिनका ब्याज कवरेज 1 से भी कम है। इन निष्कर्षों पर पहुंचने में जो मान्यताएं हैं उनके बारे में उचित प्रश्न उठ सकते हैं किंतु इसमें निहित निर्देशों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

### कमजोर वित्तीय क्षेत्र के परिणाम क्या हो सकते हैं ?

8. इसका उत्तर मैं थोड़ा अलग तरीके से देना चाहता हूँ। वित्तीय क्षेत्र जोखिम को बांट लेता है क्योंकि वह सूचनापरक और लेनदेन लागत को कम करता है। एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र में मजबूत वित्तीय बिचौलिये होते हैं तथा व्यापक और गहन वित्तीय बाजार होता है। एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र में चलनिधि और परिपक्वता का उधारकर्ताओं तथा बचतकर्ताओं के बीच रूपांतरण बड़ी कुशलता से संपन्न होता है। ऐसे बाजार में, बचतकर्ता अपनी अधिशेष राशि वित्तीय बिचौलिये को देने के प्रति आश्वस्त रहता है और जिसे उत्पादक आस्तियां बनाने के लिए न्यूनतम लागत पर उधार लिया एवं निवेश किया जा सकता है। इससे गुणात्मक (मल्टीप्लायर) प्रभाव पैदा किया जा सकता है और बचतकर्ता तथा उधारकर्ता दोनों के लिए दौलत एवं समृद्धि कमाई जा सकती है और यह संपदा पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सृजित की जा सकती है। खासतौर से ईएमई के मामले में, जिनमें ऋण बाजार मुख्यतया बैंकजन्य होता है, संसाधनों के कुशल आबंटन की संरचना सरकार के प्रयासों का केंद्र बिंदु है जो रोजगार पैदा करने तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में होता है। इसके विपरीत, एक कमजोर वित्तीय क्षेत्र में बिचौलिये कमजोर होते हैं और वित्तीय बाजार छिछला होता है जो अनिवार्यतः संकटग्रस्त होता है क्योंकि संसाधनों का आबंटन कुशलतापूर्वक नहीं किया जाता है तथा जोखिम उठाने का आचरण समानुपातिक नहीं होता है। इसलिए एक कमजोर वित्तीय क्षेत्र में अत्यधिक लीवरेज्ड कारपोरेट्स और/अथवा अत्यधिक कर्जदार व्यक्ति होंगे। एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के अभाव में व्यक्ति बचत करना बंद कर देता है अथवा उसका रख भौतिक आस्तियों की ओर होता है जिससे निवेश नहीं हो पाता और फलस्वरूप विकास रुक जाता है और साथ ही आस्तिमूल्य अस्थायी हो जाते हैं।

9. एक कमजोर वित्तीय प्रणाली से अर्थव्यवस्था तथा देश को हानिकारक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। डालास फेडरल रिजर्व रिसर्चर्स टायलर एटकिन्सन, डेविड लुटरेल एंड हार्वे रोजेनब्लम ने अपने पेपर 'वह कितना खराब था? 2007-09 के वित्तीय संकट की लागतें और परिणाम' में लिखा है कि इस संकट में आर्थिक उत्पादन और वित्तीय संपदा का भारी नुकसान हुआ, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े हैं तथा बढ़ती बेरोजगारी से कौशल क्षीण हुआ है, सरकारी हस्तक्षेप बढ़े हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण लागतें आई हैं। उनके आकलन के अनुसार केवल अमरीकी अर्थव्यवस्था का ही कुल नुकसान तकरीबन 14 ट्रिलियन अमरीकी डालर हुआ था जो भारत की जीडीपी का लगभग 7 गुना था।

10. अमरीका में समस्याग्रस्त आस्ति राहत कार्यक्रम (टीएआरपी) के विशेष महानिरीक्षक की मार्च 2012 की तिमाही रिपोर्ट में यह दिया गया है कि 2008 के वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए अमरीकी सरकार का सकल परिव्यय 4.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर था, जबकि अमरीकी तिजोरी, फेडरल रिज़र्व और अन्य अमरीकी सरकारी एजेंसियों की कुल गारंटी 16.9 ट्रिलियन अमरीकी डालर थी। इसी प्रकार यू.के. राष्ट्रीय लेखा-परीक्षा कार्यालय ने बताया कि मात्र 2008 के वित्तीय संकट से यूके के करदाताओं को उबारने के लिए 955 बिलियन स्टर्लिंग की लागत आई थी।

11. इस प्रकार ऊपर दी गई संख्याओं से वित्तीय संकट से हुए आर्थिक नुकसान का अंदाजा लगता है। ये संख्याएं भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अनुमानित हैं। जैसाकि पुरानी कहावत है कि 'रोकथाम, इलाज से बेहतर है, और रेगुलेटरी सुधार प्रक्रिया का यह प्रयास होना चाहिए कि वह वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाए और उसे इस प्रकार तैयार करे कि वह किसी भी संकट का सामना कर सके।

12. सवाल यह है कि वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को स्वस्थ बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इससे पहले कि मैं यह बात करूं कि संकट के बाद बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए, मैं यह रेखांकित करना चाहता हूँ कि संपूर्ण विकसित विश्व में विभिन्न सरकारों/केंद्रीय बैंकों द्वारा किस प्रकार से मौद्रिक प्रोत्साहन दिया गया। अमरीका, यूरोप, यूके और जापान के मौद्रिक नीति निर्माताओं ने इस मंदी से बाहर निकलने के लिए विस्तारकारी मौद्रिक नीति को अपनाया। लेकिन इन प्रयासों का अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाया है क्योंकि ये देश अभी भी संकट से पूर्व उनकी विकास दर के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। जापान तो अपने तीसरे 'खो चुके दशक' में प्रवेश कर चुका है और अभी भी विकास का मार्ग तलाश रहा है। इसके अलावा, जैसाकि अब तक यह सिद्ध हो चुका है कि ढीली मौद्रिक नीति प्रसिद्ध युद्ध 'महाभारत' के 'चक्रव्यूह' के समान है जिसमें प्रवेश करना तो आसान था लेकिन उससे बाहर निकलना कठिन था।

13. अब मैं बैंकिंग क्षेत्र में किए जाने वाले सुधार के बारे में बात करूंगा।

### वैश्विक सुधार

14. यूरोप और अमरीका के बैंक वित्तीय संकट में घिर गए और उनके तुलनपत्र अत्यधिक लीवरेज्ड थे। उनकी इक्विटी बहुत ही कम थी और तुलनपत्र निराधार तरीके से बनाए गए थे ताकि जटिल

व्युत्पन्नी लिखतों में किए गए अपने निवेशों को बट्टे खाते डाल सकें। विकासशील देशों में स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन इन बाजारों में स्थित बैंकों पर भी प्रभाव पड़ने लगा क्योंकि वास्तविक अर्थव्यवस्था की पीड़ा धीरे-धीरे वित्तीय अर्थव्यवस्था को कष्ट पहुंचाने लगी। इसकी पृष्ठभूमि में ये बातें थीं जिनकी वजह से बहुपक्षीय मानक निर्धारक निकायों द्वारा रेगुलेटरी सुधार प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया गया ताकि संकट-पूर्व काल की जो अतिशयता थी उसे रोका जा सके। सुधार प्रक्रिया की प्रमुख बातें जो कार्यान्वित हो चुकी हैं/इस समय जिनपर बातचीत चल रही है वे इस प्रकार हैं :

- बासेल III पूंजी निर्धारण, साथ ही पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर
- चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)
- लीवरेज अनुपात
- कुल हानि वहन क्षमता (टीएलएसी), यह कार्य प्रगति पर है, जिसका उद्देश्य जी-सिब/जी-सीज/जी-एनबीएनआई के लिए भारी नुकसान वहन करने की अपेक्षा तथा समाधान ढांचा तैयार करता है।
- आभासी बैंकिंग (शैडो बैंकिंग) का विनियमन
- ओटीसी व्युत्पन्नी बाजार का सुधार और सीसीपी का समाधान
- बैंकों के रेगुलेटरी पूंजी अनुपात में अत्यधिक भिन्नता की समस्या को हल करने के लिए रेगुलेटरी पूंजी के आकलन हेतु एक मानकीकृत, गैर-माडलीकृत दृष्टिकोण (एक विचार)
- क्षतिपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से जोखिम उठाने के अनुरूप बनाना, कराधान का प्रावधान
- बेंचमार्क निर्धारण में पारदर्शिता

15. इन सुधार के उपायों का निहित उद्देश्य यह है कि दबाव के समय वित्तीय संस्थाओं को उबारने के लिए करदाताओं के धन पर निर्भरता को समाप्त करना।

### भारतीय स्थिति

16. बैंक-प्रधान अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत के आर्थिक विकास के लिए एक स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र का होना अनिवार्य है। भारतीय रिज़र्व

बैंक अपने विनियमन के माध्यम से एक सुदृढ़ तथा कुशल बैंकिंग प्रणाली विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों के सदस्य के रूप में इस समय हम न केवल विश्व स्तर पर सहमत रेगुलेटरी सुधार को कार्यान्वित कर रहे हैं बल्कि विश्व स्तर पर कतिपय जोखिमों की ओर ध्यान दिलाए जाने से बहुत पहले सक्रिय रूप से समष्टि-विवेकपूर्ण उपायों जैसे बैंकों के भू-संपदा एक्सपोजर पर अधिक जोखिम भार, व्युत्पन्नी और प्रतिभूतिकरण लेनदेन में पैदा होने वाले जोखिमों तथा कारपोरेट्स के पेंचदार असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए लागू कर चुके हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक में हम हमेशा ऐसे रेगुलेशन की आवश्यकता के प्रति सचेत रहते हैं और उससे तत्काल बनाते हैं ताकि आने वाले जोखिम को दूर किया जा सके और इस प्रकार हाल में किए गए अनेक सुधारात्मक उपाय इसी भावना से किए गए हैं।

### भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल में किए गए उपाय

17. बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व-शर्त यह होती है कि वे अपने मौजूदा तथा भावी ग्राहकों के उधार दायित्वों को पूरा करने के लिए लाभप्रद एवं मालदार स्थिति में बने रहें। इसी संदर्भ में कुछ दिन पहले निम्नलिखित रेगुलेटरी कार्रवाई प्रारंभ की गई है जिसमें दो बातों का मिश्रण रखा गया है, विवेकपूर्ण रेगुलेशन और विकास को समर्थन देने के लिए उचित प्रोत्साहन तथा उचित जोखिम प्रबंधन:

- 'वित्तीय दबावग्रस्तता की शीघ्र पहचान, उधारदाताओं के लिए समाधान हेतु तत्परता उपाय और उपयुक्त रूप से वसूली : अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए ढांचा जिसमें संयुक्त उधारकर्ता मंच (जेएलएफ)' का निर्माण शामिल है, सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी), 'परियोजना ऋणों का पुनर्वित्त', 'बैंकों द्वारा एनपीए की बिक्री', के संबंध में दिशानिर्देश ताकि वित्तीय दबावग्रस्तता की शीघ्र पहचान की जा सके/उनका समाधान किया जा सके।
- बैंकों को दीर्घकालीन जेस्टेशन-पीरियड वाली परियोजनाओं के लिए कर्ज की चुकौती हेतु अवधि को बढ़ाने की अनुमति दी गई ('5/25' योजना)
- बैंकों को स्ट्राटेजिक ऋण परिवर्तन (एसडीआर) हेतु कदम उठाने योग्य बनाया गया उन्हें यह अधिकार दिया गया कि यदि उधारकर्ता पुनर्चना पैकेज के अंतर्गत दी गई शर्तों को पूरा नहीं कर पाता तो वे अपने बकाया ऋणों को बड़े इक्विटी स्टेक में बदल सकते हैं।

- धोखाधड़ी निगरानी ढांचे में विस्तार
- दीर्घकालीन इन्फ्रा परियोजनाओं को वित्त की उपलब्धता के लिए दीर्घकालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बाण्ड जारी करना।
- पुनर्चना के संबंध में सहिष्णुता (फारबीअरेंस) को बहाल करना।

कुछ अन्य रेगुलेटरी उपाय जैसे एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा में संशोधन और डी-सिब की पहचान करना आदि प्रारंभ किए गए।

### कायम रखने योग्य विकास के संवर्धन में लेखा-परीक्षा समुदाय की भूमिका

18. अब मैं यहां उपस्थित लेखापरीक्षकों के समुदाय को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आपकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि आप बैंकों तथा उधारकर्ताओं जिन्हें बैंक उधार देते हैं के तुलनपत्र की लेखापरीक्षा करके बैंकिंग क्षेत्र को स्वस्थ बनाए हुए हैं। लेकिन मैं अपनी बात हलके अंदाज में शुरू करना चाहता हूँ। मैं एआइजी के उपाध्यक्ष **जैकब फ्रेन्केल** को उद्धृत करना चाहता हूँ जिन्होंने वित्तीय संकट के बाद एक बार कहा था, '**तुलनपत्र के बायें हिस्से (Left side) में कुछ भी सही नहीं (nothing right) है और तुलनपत्र के दायें हिस्से (right side) में कुछ भी शेष (left) नहीं बचा है। किंतु दोनों एक-दूसरे के समान हैं। इसलिए लेखांकन के हिसाब से हम सब दुरुस्त हैं।**' मुझे यकीन है कि हम नहीं चाहते कि हमारी लेखांकन प्रणाली इस प्रकार से दुरुस्त हो।

19. लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में बाजार का भरोसा कायम रखने में बाहरी लेखा-परीक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम पूरी अर्थव्यवस्था में बैंक के वित्तीय मध्यस्थता के कार्य को लें तो बैंकिंग उद्योग के संबंध में उनकी यह भूमिका खास तौर से वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण (सितंबर 2012) से संबंधित बासेल समिति के प्रमुख सिद्धांतों में से प्रमुख सिद्धांत संख्या 27 में यह उल्लेख किया गया है कि पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करता है कि बैंक तथा बैंकिंग समूह पर्याप्त और भरोसेमंद अभिलेख बनाए रखते हैं, लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से स्वीकार्य होते हैं और वार्षिक आधार पर सूचनाएं प्रकाशित करते हैं जिससे उनकी वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन का भलीभांति पता चलता है और उनमें बाह्य लेखापरीक्षक के स्वतंत्र अभिमत दिए गए होते हैं।

20. लंबे समय से हम अनेक लेखांकन संबंधी घोटाले देखते आ रहे हैं, जिनमें से बिलकुल ताजा घटना तोशिबा के संबंध में है। यह

माना जाता है कि तोशिबा को 2008 से लेकर पिछले सात वर्ष के अपने कर-पूर्व लाभ के आंकड़ों में 152 बिलियन येन (1.2 बिलियन अमरीकी डालर) तक का संशोधन करना पड़ेगा। इस राशि में उक्त अवधि के दौरान कुल कर-पूर्व लाभ की लगभग 30 प्रतिशत राशि शामिल है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लेखांकन गड़बड़ी में शीर्ष कार्यपालक शामिल थे जिसमें हानि की रिपोर्टिंग में विलंब करते हुए परियोजना लागतों को कम दिखाते हुए आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था। इस प्रकार की असफलता निश्चित रूप से यह दिखाती है कि लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में खामियां हैं।

21. लेखांकन गोलमाल की एक अन्य घटना रोजनेफ्ट के संबंध में देखी गई थी, जो रूस शासन द्वारा नियंत्रित एक एनर्जी समूह है, जिसने एक बोली में अपने परिणामों में रूबल में गिरावट के प्रभाव को कम दिखाने के लिए विदेशी करेंसी में उतार-चढ़ाव के लेखांकन तरीके को ही बदल दिया था। कंपनी ने ऐसे उतार-चढ़ाव घटित हो जाने के बाद उसके प्रभाव को रिकॉर्ड करना प्रारंभ किया, बजाय इसके कि उसके अस्थायी प्रभावों को प्रत्येक तिमाही में दर्ज किया जाता। मुझे नहीं पता कि लेखापरीक्षा समुदाय इस मामले को किस दृष्टि से देखेगा किंतु यह मामला विश्लेषकों के लिए निश्चित रूप से दिलचस्पी का विषय होगा और इसमें कंपनी की वित्तीय जानकारी को सही एवं उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया था।

22. लेखापरीक्षकों से अपेक्षित है कि वे पेशेवराना नैतिकता के उच्चतम मानक कायम रखें और यह सुनिश्चित करें कि जिन उद्यमों के वित्तीय विवरणों की वे लेखापरीक्षा कर रहे हैं उसमें सतत आधार पर प्रचलित कार्य-स्थिति की सही और उपयुक्त तस्वीर पेश की जाती है। एक पेशेवर के तौर पर आपको अत्यधिक सतर्क रहना होगा जब आप ऐसे क्षेत्रों की लेखा-परीक्षा कर रहे हों जिनमें: (ए) महत्वपूर्ण प्रबंधन संबंधी आकलन एवं निर्णय शामिल हों, खासतौर से ऐसे आकलन जिनमें: अत्यधिक अनिश्चितताएं होती हों; (बी) ऐसे लेनदेन जो बार-बार न होते हों या असामान्य स्वरूप के हों, अथवा (सी) ऐसे मामले जिनमें धोखाधड़ी या गलतियां होने की संभावना हो और जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण बार-बार हो रहे हों।<sup>1</sup>

23. जैसाकि मैंने पहले कहा है कि उधार देने का कारोबार और ऋण का मूल्यांकन काफी हद तक उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत तुलनपत्र पर ही निर्भर करते हैं और इस प्रकार कल्पना से बनाए गए लेखा विवरण

गलत निष्कर्ष पर ले जा सकते हैं और उद्यमों को अनपेक्षित तरीके से वित्त मिलता रहेगा। बैंक काफी हद तक स्टॉक तथा आस्ति लेखा-परीक्षा, संगामी लेखा-परीक्षा तथा न्यायिक लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों पर निर्भर होते हैं। जब हम कारपोरेट के तुलनपत्र को देखते हैं और उसमें लीवरेज के स्तर को समझने की कोशिश करते हैं तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कारपोरेट के ढांचे को देखें और पूंजी को किस तरह सहयोगी संस्थाओं की ओर ले जाया जा रहा है। यदि इन कार्यों को अच्छी तरह पूरा किया जाता है तो यह न केवल बैंक के वित्तीय विवरणों को सुदृढ़ करेगा बल्कि इससे एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के सृजन में भी सहायता मिलेगी।

24. कई लोगों का यह तर्क है कि हाल में घटित विश्व का वित्तीय संकट लेखांकन नियमों की देन है। जहां व्यापक सहमति इस बात पर है कि लेखांकन नियम बैंक-व्यवहार के अहम निर्धारक होते हैं, इसलिए संकट के लिए किसी एक कारक को दोष देना नासमझी होगी क्योंकि विशिष्ट प्रणाली और उनका रेगुलेटरी अपेक्षा के साथ परस्पर कार्य करने की प्रक्रिया को बहुत कम समझा जा सका है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आइएफआरएस) के अंतर्गत उचित मूल्य लेखांकन प्रणाली के इस्तेमाल के प्रभाव तथा हानि प्रावधानीकरण के घटित हानि दृष्टिकोण के मामले इस संबंध में देखे जाने होंगे। इन दोनों की आलोचना की गई है कि ये बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया में चक्रीय-व्यवहार के विरुद्ध है अर्थात् प्रचुरता को बढ़ाना और सुधार की स्थिति में निवेश को और भरना तथा जिससे घटता हुआ चक्र बनता है और ऋण-चक्र के उतार पर निवेश को जकड़ लेता है।<sup>2</sup> इसके विपरीत रेगुलेशन इस प्रकार बनाया गया है ताकि वह 'चक्र के समाप्त होने तक बना रहे। मैं इस बहस की गहराई में नहीं जाना चाहता, बल्कि इसकी कुछ बारीकियों पर फोकस करना चाहता हूँ जिसे आइएफआरएस का कार्यान्वयन, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में त्याग देगा।

### आइएफआरएस का कार्यान्वयन और विचारणीय बारीकियां

25. बैंकिंग प्रणाली के लिए आइएफआरएस के कार्यान्वयन से क्या तात्पर्य है? प्रश्न यह है कि आइएफआरएस के साथ-साथ विवेकपूर्ण रेगुलेशन किस तरह बना रहेगा? आइएफआरएस के अंतर्गत प्रस्तावित हानि का आकलन, प्रभावी ब्याज दर आधार पर ब्याज-आय का आकलन तथा परिचालन हेतु बहुविध प्रणाली की मौजूदगी

<sup>1</sup> बीसीबीएस पेपर : बैंकों की बाह्य लेखा-परीक्षा (मार्च 2014)

<sup>2</sup> बीसीबीएस वर्किंग पेपर : लेखांकन और रेगुलेशन का पारस्परिक प्रभाव और उसका बैंक के व्यवहार पर असर: साहित्य समीक्षा (जनवरी 2015)

और विभिन्न पोर्टफोलियो का लेखांकन का अर्थ यह होगा कि आईटी प्रणालियों को उन्नत बनाना होगा/आइएफआरएस की ओर जाने के लिए उन्हें पुनः इसके अनुरूप बनाना होगा। बैंकों को वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए वित्तीय लेखांकन और कर-आकलन की नीतियों को बदलते समय उसकी चुनौतियों से पार पाना होगा।

26. जैसे-जैसे आइएफआरएस के कार्यान्वयन की तारीख नजदीक आ रही है, उस संबंध में कई चिंता वाले प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर ढूंढे जाने जरूरी हैं।

- i) लेखों का समेकन किस प्रकार किया जाएगा यदि मूल संस्था इंड एस के अंतर्गत है लेकिन उनकी सहयोगी संस्थाएं इसके अंतर्गत नहीं हैं ?
- ii) यदि एक सहयोगी संस्था का लेखा इंड एस में बनाया जाएगा जो उसी तरह मूल संस्था के लिए नहीं होगा (उदा. के लिए एक एनबीएफसी होल्डिंग कंपनी) तो स्थिति क्या होगी ?
- iii) आप इक्विटी को 'पुट ऑप्शन' के साथ कैसे बरतेंगे।
- iv) किस प्रकार से फर्मों के लेखा की समग्र अवधि के लिए तुलना की जा सकेगी ?

27. यह संभव है कि उचित मूल्य लेखांकन को अंगीकार करने में प्रारंभ में फर्मों के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़े और फलस्वरूप फर्म और बैंक दोनों के तुलनपत्र प्रभावित हो सकते हैं।

## समापन

28. आर्थर एंडरसन, एक लेखांकन फर्म थी जो अब बंद हो चुकी है जिसने एनरॉन की लेखा-परीक्षा की थी, के पूर्व वकील जिम पीटरसन का कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था '**एक लेखा-परीक्षक का अधिकांशतः आमतौर पर यही विचार होता है कि वास्तव में 'यह वित्तीय जानकारी कमोबेश ठीक है'**'। मुझे यकीन है कि श्री पीटरसन ने जो बात कही है उसकी तुलना में यह बैठे लेखांकन समुदाय के लोग कहीं अधिक सार्थक और बेहतर तरीके से कार्य करते हैं।

29. मैं यह बात दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि कायम रखने योग्य विकास के लिए एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र का होना अनिवार्य है। वित्तीय क्षेत्र विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र की शक्ति उसके स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो, कारपोरेट तथा खुदरा दोनों से तथा मजबूत निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त होती है। लेखांकन मानक तथा लेखा-परीक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है कि बैंक इस प्रकार के पोर्टफोलियो विकसित कर सकें। निःसंदेह, रेगुलेशंस, लेखांकन मानक तथा क्रेडिट-रेटिंग के बीच जटिल किंतु अनिवार्य संबंध है।

30. मुझे उम्मीद है कि मैंने जो मुद्दे यहां उठाए हैं उनके बारे में यह सम्मेलन विभिन्न हितधारकों को मार्गदर्शन देने तथा उपयुक्त उत्तर तलाश करने में सफल होगा। मैं पुनः आइसीएआइ को मुझे यहां आमंत्रित करने और इस अवसर पर अपने विचार का आदान-प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ तथा सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।